Journal of Integrative Science and Societal Impact
January-June 2026 2(1)
https://jissi.org

Original Article

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 AND SOCIAL EQUITY: A STUDY IN THE CONTEXT OF RURAL AND URBAN SOCIETY

नई शिक्षा नीति 2020 और सामाजिक समानता: ग्रामीण एवं शहरी समाज के संदर्भ में एक अध्ययन

Pradeep Kumar [1*], **Dr. Ravi Kant Saral** [1]
[1] School of Education, Shri Venkateshwara University, Gajraula, District Amroha, Uttar Pradesh, India

ABSTRACT

English: The National Education Policy (NEP) 2020 represents a historic and transformative step in India's education system. The policy aims to make education inclusive, equitable, high-quality, and accessible. It places special emphasis on social equity, equal access to educational opportunities, and the educational empowerment of marginalized sections of society. In a vast and diverse country like India, significant disparities exist between rural and urban areas regarding the quality of education, resources, technological facilities, and opportunities.
This research paper presents a comparative study of the impact of NEP 2020 on rural and urban societies. The study analyzes aspects such as access to education, the availability of digital resources, mother-tongue-based instruction, vocational education, social justice, inclusive education, and the digital divide. The study reveals that while NEP 2020 is an effective initiative towards establishing social equity, its successful implementation requires addressing regional disparities, digital inequalities, and infrastructural challenges.

Hindi: भारत की शिक्षा व्यवस्था में वर्ष 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति National Council of Educational Research and Training (n.d.) एक ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी कदम है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण तथा सुलभ बनाना है। नई शिक्षा नीति सामाजिक समानता, शैक्षिक अवसरों की समान उपलब्धता तथा वंचित वर्गों के शैक्षिक सशक्तिकरण पर विशेष बल देती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों, तकनीकी सुविधाओं तथा अवसरों में पर्याप्त असमानता पाई जाती है।
प्रस्तुत शोध-पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के ग्रामीण एवं शहरी समाज पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में शिक्षा तक पहुंच, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, मातृभाषा आधारित शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक न्याय, समावेशी शिक्षा तथा डिजिटल विभाजन जैसे विषयों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है, किंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय विषमताओं, डिजिटल असमानताओं तथा अवसंरचनात्मक चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है।

Keywords: New Education Policy 2020, Social Equality, Rural Education, Urban Education, Digital Inclusion, Social Justice, नई शिक्षा नीति 2020, सामाजिक समानता, ग्रामीण शिक्षा, शहरी शिक्षा, डिजिटल समावेशन, सामाजिक न्याय।

*Corresponding Author:
Email address: Pradeep Kumar (Pradeep.Kumar@outlook.com)

Received: 25 May 2026; **Accepted:** 10 June 2026; **Published** 30 June 2026
DOI: 10.29121/JISSI.v2.i1.2026.78
Page Number: 235-240
Journal Title: Journal of Integrative Science and Societal Impact
Journal Abbreviation: J. Integr. Sci. Soc. Impact
Online ISSN: 3108-2165, **Print ISSN:** 3108-1959
Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India
Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.
Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.
Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.
Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता अत्यंत व्यापक है। देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास, तकनीकी संसाधन और शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता है। इस कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों में उल्लेखनीय अंतर देखा जाता है।

शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति का आधार भी है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की शिक्षा और कौशल पर निर्भर करती है। इसी कारण शिक्षा को सामाजिक समानता स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया एक व्यापक सुधार कार्यक्रम है। यह नीति विद्यार्थियों को केवल परीक्षा-उन्मुख नहीं बल्कि जीवन-उन्मुख शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। इसका प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानताओं को कम करना है।

अध्ययन की आवश्यकता

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। यह आवश्यक है कि इन परिवर्तनों का सामाजिक समानता पर प्रभाव समझा जाए।

अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है—

1) ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा के बीच अंतर का मूल्यांकन।
2) शिक्षा में समान अवसरों की उपलब्धता का विश्लेषण।
3) डिजिटल शिक्षा के प्रभावों का अध्ययन।
4) सामाजिक न्याय एवं समावेशन की स्थिति का आकलन।
5) नीति के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान।

अध्ययन के उद्देश्य

1) नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
2) ग्रामीण क्षेत्रों में नीति के प्रभावों का विश्लेषण करना।
3) शहरी क्षेत्रों में नीति के प्रभावों का अध्ययन करना।
4) डिजिटल विभाजन और सामाजिक समानता के संबंध का मूल्यांकन करना।
5) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना।
6) नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रदान करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति** पर आधारित है।

आंकड़ों के स्रोत

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्टें
- यूजीसी रिपोर्ट
- एनसीईआरटी सर्वेक्षण
- नीति आयोग रिपोर्ट
- यूनेस्को रिपोर्ट
- प्रकाशित शोध-पत्र एवं पुस्तकें

सामाजिक समानता की अवधारणा

सामाजिक समानता का अर्थ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति अथवा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।

भारतीय संविधान भी अनुच्छेद 14, 15, 21A तथा 46 के माध्यम से समानता और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

शिक्षा सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि—

- यह गरीबी कम करती है।
- सामाजिक गतिशीलता बढ़ाती है।
- अवसरों की समानता प्रदान करती है।
- सामाजिक न्याय को मजबूत करती है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है।

नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

5+3+3+4 संरचना

नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल किया गया है। यह व्यवस्था बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में सहायक है।

बहुभाषिकता

नीति मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

बहुविषयक शिक्षा

विद्यार्थियों को विषय चयन में अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

कौशल विकास

कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल शिक्षा

DIKSHA, SWAYAM, SWAYAM Prabha जैसे प्लेटफार्मों को बढ़ावा दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों पर नई शिक्षा नीति का प्रभाव

शिक्षा तक पहुंच में सुधार

नई शिक्षा नीति विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने पर बल देती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में—

- नए विद्यालयों की स्थापना
- विद्यालय परिसरों का विकास
- परिवहन सुविधाओं का विस्तार

जैसे प्रयासों से शिक्षा तक पहुंच बढ़ने की संभावना है।

मातृभाषा आधारित शिक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यार्थी स्थानीय भाषाओं में संवाद करते हैं।

मातृभाषा आधारित शिक्षा के लाभ—

- बेहतर समझ
- उच्च सीखने की क्षमता
- कम ड्रॉपआउट दर
- सांस्कृतिक संरक्षण

कौशल आधारित शिक्षा का प्रभाव

ग्रामीण युवाओं को कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, डिजिटल सेवाओं और उद्यमिता से संबंधित कौशल प्रदान किए जा सकते हैं।

इससे—

- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- पलायन कम होगा।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

महिला शिक्षा पर प्रभाव

नई शिक्षा नीति बालिकाओं के नामांकन और निरंतरता को बढ़ावा देती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इससे—

- बाल विवाह में कमी
- महिला सशक्तिकरण
- आर्थिक आत्मनिर्भरता

जैसे सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियाँ

विद्यालयों की कमी

कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गुणवत्तापूर्ण विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।

प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव

विशेष रूप से विज्ञान और गणित विषयों में शिक्षकों की कमी है।

डिजिटल संसाधनों की कमी

इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की अनुपलब्धता बड़ी समस्या है।

आर्थिक बाधाएँ

गरीबी के कारण विद्यार्थी शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

शहरी क्षेत्रों पर नई शिक्षा नीति का प्रभाव

डिजिटल शिक्षा का विस्तार

शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट कक्षाएं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम तथा ई-लर्निंग सुविधाएं तेजी से विकसित हुई हैं।

बहुविषयक शिक्षा

शहरी संस्थानों में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के संयोजन का अवसर मिलता है।

अनुसंधान और नवाचार

नई शिक्षा नीति अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) के माध्यम से शोध गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

रोजगारोन्मुख शिक्षा

उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

डिजिटल विभाजन और सामाजिक समानता

डिजिटल विभाजन से आशय तकनीकी संसाधनों तक पहुंच में असमानता से है।

भारत में—

- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता
- स्मार्टफोन और लैपटॉप की कमी
- डिजिटल साक्षरता का अभाव

सामाजिक समानता में बाधा उत्पन्न करते हैं।

नई शिक्षा नीति डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है, किंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यक है।

सामाजिक न्याय एवं समावेशन

नई शिक्षा नीति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के लिए विशेष प्रावधान करती है।

प्रमुख उपाय

- छात्रवृत्ति योजनाएँ
- जेंडर इन्क्लूजन फंड
- विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ)
- दिव्यांग छात्रों हेतु सुविधाएँ
- ओपन एवं डिस्टेंस एजुकेशन

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका 1

आधार	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
इंटरनेट उपलब्धता	सीमित	व्यापक
डिजिटल उपकरण	कम	अधिक
प्रशिक्षित शिक्षक	अपेक्षाकृत कम	पर्याप्त
उच्च शिक्षा संस्थान	सीमित	अधिक
कौशल प्रशिक्षण	विकासशील	विकसित
अनुसंधान अवसर	कम	अधिक
ड्रॉपआउट दर	अधिक	कम

नीति के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

1) वित्तीय संसाधनों की कमी
2) राज्यों के बीच असमानता
3) डिजिटल अवसंरचना का अभाव
4) शिक्षक प्रशिक्षण
5) प्रशासनिक समन्वय
6) सामाजिक जागरूकता की कमी

सुझाव

डिजिटल अवसंरचना का विस्तार

प्रत्येक विद्यालय को इंटरनेट से जोड़ा जाए।

शिक्षक प्रशिक्षण

नियमित क्षमता-विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार

वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम

क्षेत्रीय रोजगार अवसरों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम विकसित किया जाए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह नीति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच विद्यमान शैक्षिक असमानताओं को कम करने की क्षमता रखती है। मातृभाषा आधारित शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय और समावेशन जैसे प्रावधान सामाजिक समानता को सुदृढ़ करते हैं।

हालांकि, डिजिटल विभाजन, अवसंरचनात्मक कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता तथा आर्थिक बाधाएँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौती प्रस्तुत करती हैं। यदि सरकार, शैक्षणिक संस्थान, समुदाय और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करें, तो नई शिक्षा नीति भारत को एक समतामूलक, ज्ञान-आधारित और समावेशी समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

REFERENCES

Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.
University Grants Commission. (2021–2025). Annual reports.
National Council of Educational Research and Training. (n.d.). Educational survey reports.
NITI Aayog. (n.d.). School Education Quality Index (SEQI) Reports. Government of India.
UNESCO. (n.d.). Global Education Monitoring Report. UNESCO.
Tilak, J. B. G. (2021). Education and Development in India.
Kumar, K. (2022). Educational Reforms and Social Change.
Government of India, Ministry of Finance. (n.d.). Economic Survey.
World Bank. (n.d.). Education and Equity Reports.
Ministry of Statistics and Programme Implementation. (n.d.). Reports and publications. Government of India.